दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शुक्रवार 03 अप्रैल 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 183

महत्वपूर्ण एवं खास

प्रधानमंत्री ने लोगों को रामनवमी की दी शुभकामनाएं

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रामनवमी के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, रामनवमी के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्रीराम! कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के बीच देशभर में आज घरों में ही रामनवमी मनाई जा रही है। रामनवमी पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि चैत्र मास की शुक्लपक्ष नवमी को रामनवमी का त्योहार मानाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था।

कुलगाम में आतंकियों ने की दो की हत्या

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार रात को आतंकवादियों ने गोली मारकर दो लोगों की हत्या कर दी। गोली लगने से दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने रात करीब 10:45 बजे कुलगाम के नंदीमार्ग इलाके में गुलाम हसन वागाय और सिराजुद्दीन गोरसी को उनके घरों पर गोली मार दी। उन्होंने बताया कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी। पुलिस मामले में जांच कर रही है। बता दें कि मृतकों मे एक भाजपा कार्यकर्ता बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस या किसी भाजपा नेता ने इसकी पुष्टि नहीं की है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक सिराजुदीन गोरसी कुछ समय पहले ही भाजपा में शामिल हुआ था। कुछ वर्ष पूर्व आतंकियों ने उसकी मां और बीबी को भी निशाना बनाया था। कुलगाम जिले में दमहाल हांजीपोरा के साथ सटे नाडीमर्ग में रात के अंधेरे में स्वचालित हथियारों से लैस चार से पांच आतंकी दाखिल हुए।

तब्लीगी गतिविधियों में लिप्त 960 विदेशी ब्लैकलिस्टेड

» आवश्यक कानूनी कार्यवाई होगी

नईदिल्ली (आरएनएस)। गृह मंत्रालय द्वारा पर्यटक वीज़ा पर तब्लीगी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण 960 विदेशियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है और साथ ही उनका भारतीय वीजा भी रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने तब्लीगी जमात, निजामुद्दीन के मामले में दिल्ली पुलिस और अन्य सम्बंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को विदेशी अधिनियम,1946 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 960 विदेशियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाई करने के निर्देश दिए हैं।

कोरोना की लड़ाई में डॉक्टरों ने मांगी सीआरपीएफ की सुरक्षा

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना की लड़ाई में जुटे डॉक्टरों के साथ हो रही अभद्रता और हमले रोकने के लिए अब डॉक्टरों ने सीआरपीएफ सुरक्षा की मांग की है। एम्स की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (आरडीए) ने इस बाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। हैदराबाद में जिस तरह डॉक्टरों पर हमला हुआ है, उसके बाद डॉक्टरों में भारी रोष है। एम्स की आरडीए के अध्यक्ष डॉ. आदर्श प्रताप सिंह और महासचिव डॉ. श्रीनिवास राजकुमार ने अमित शाह को लिखे अपने पत्र में कहा है कि कोरोना को हराने के लिए डॉक्टर दिनरात काम कर रहे हैं। इस लड़ाई में कई डॉक्टर भी संक्रमित हो गए हैं। इसके बावजूद डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। डॉक्टरों की मांग है कि उनके परिसरों और अस्पतालों में सीआरपीएफ सुरक्षा लगाई जाए। सीआरपीएफ सुरक्षा के बाद डॉक्टर खुद को सुरक्षित महूसस कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना मरीजों की जांच में लगे डॉक्टरों एवं दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ को सभी जरूरी उपकरण मुहैया कराएं जाएं। गौरतलब है कि इससे पहले विदेशों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद वहां से भारतीयों को स्वदेश लाने वाले पायलट और क्रू मेंबर के साथ भी अभद्रता करने जैसी खबरें सामने आई थी। जहां पर ये लोग रहते हैं, वहां इन्हें कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही हैं।

लॉकडाउन सरकार का जल्दबाजी में लिया गया फैसला: सोनिया

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केंद्र सरकार की तैयारियों पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने 21 दिन के लॉकडाउन का फैसला जल्दबाजी में लिया है। जबकि इससे पहले सोनिया ने खुद इस फैसले का समर्थन किया था।

कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने यह आरोप गुरुवार को हुई कांग्रेस की वर्किंग कमिटी की बैठक में लगाया, जिनके साथ राहुल गांधी ने भी लॉकडाउन पर सवाल उठाए और प्रवासी कामगारों को हुई दिक्कतों का जिक्र किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस मीटिंग में सोनिया ने कहा कि लॉकडाउन जरूरी हो सकता है लेकिन इसके अनियोजित क्रियान्वयन से लाखों प्रवासी श्रमिकों को परेशानी और तकलीफ उठानी पड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से बने हालात से निपटने के लिए सरकार को एक विस्तृत रणनीति बनाना चाहिए थी।

सोनिया ने कहा टेस्टिंग का ऑप्शन नहीं

भारत के सामने कोरोना वायरस के रूप में एक बड़ी समस्या खड़ी है, लेकिन इसे हराने की हमारी इच्छा शक्ति ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज यह बात की है। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सोनिया गांधी का एक बयान आया। इसमें उन्होंने बताया कि यह मीटिंग बड़े स्वास्थ्य और मानवीय संकट के बीच हुई, जिसमें कोरोना वायरस पर ही चर्चा हुई। सोनिया ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए निरंतर और विश्वसनीय टेस्टिंग का कोई विकल्प नहीं है। सोनिया गांधी ने मांग उठाई कि कोरोना से जंग में लगे डॉक्टर, नर्स और बाकी मेडिकल स्टाफ को सरकार पूरा सपोर्ट करे और उन्हें सूट, एन95 मास्क जैसी जरूरी चीजें जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। सोनिया ने आगे कहा, एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य और मानवीय संकट के बीच आज हमारी मीटिंग हुई।

कोरोना संकट में समग्र रणनीति बनाए सरकार

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए समग्र रणनीति बनाए तथा 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान प्रभावित लोगों की मदद के लिए साझा न्यूनतम राहत कार्यक्रम तैयार करे।

सुप्रीम कोर्ट ने बाल संरक्षण गृहों की स्थिति का लिया संज्ञान

» कोरोना वायरस

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए देश में बाल संरक्षण गृहों की स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया है और वह शुक्रवार को इस मामले पर विचार करेगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ बाल संरक्षण गृहों में कोविड-19 संक्रमण के खतरे पर शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेगी।

शीर्ष अदालत ने 16 मार्च को देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने का संज्ञान लिया था और कहा था कि इसमें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कैदियों के बीच दूरी बनाना कठिन है। न्यायालय ने बाल सुधार गृहों और बाल संरक्षण गृहों में भी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के पहलू पर विचार किया था। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने 23 मार्च को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च स्तरीय समिति गठित करके ऐसे दोषियों और विचाराधीन कैदियों को पेरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा करने पर विचार करने के लिये कहा था जिनके अपराधों के लिए सात साल तक की सजा है। यही नहीं, न्यायालय ने कोरोना वायरस की वजह से देश भर में स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों को मध्यान्ह भोजन नहीं मिलने के मुद्दे पर भी विचार किया था।

तबलीगी जमात के लोगों ने आइसोलेशन सेंटर में डॉक्टरों व स्टाफ पर थूका

नईदिल्ली (आरएनएस)। निज़ामुद्दीन मरकज से क्वॉरेंटाइन के लिए तुग़लक़ाबाद जाने के क्रम में सड़क पर थूकने वाले तबलीगी जमात के 167 लोगों ने अब यहां डॉक्टरों और स्टाफ पर थूका और बदतमीज़ी की। रेल अधिकारियों के मुताबिक़ सभी हॉस्टल में गंदगी फैला रहे हैं और इधर-उधर घूम रहे हैं।

रेलवे के एक प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। निजामुद्दीन मरकज में

तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में से 167 को मंगलवार की शाम तुगलकाबाद में रेलवे के पृथक केंद्रों में लाया गया था। उल्लेखनीय है कि मरकज में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में से अनेक को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है और कुछ की मौत हो चुकी है।

सूत्रों ने बताया कि रेलवे के केंद्र में इन 167 लोगों को रखे जाने के बाद रेलवे कॉलोनी के लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।

» अस्थायी रोजगार के दिशानिर्देश जारी

एनसीसी कैडेट कोरोना से निबटने राष्ट्रव्यापी अभियान में होंगे शामिल

नईदिल्ली (आरएनएस)। नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) ने 'एक्सरसाइज एनसीसी योगदान'के तहत कोडिट-19 से निबटने के राष्ट्रव्यापी अभियान में नागरिक प्रशासन को मदद की पेशकश की है।एनसीसी ने इसके लिए स्वैच्छिक सेवा देन के इच्छुक अपने कैडेटों के वास्ते अस्थायी रोजगार के दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि महामारी से निपटने के कार्यो में शामिल विभिन्न एजेंसियों की ओर से चलाए जा रहे राहत प्रयासों और काम काज के तरीकों को और मजबूत बनाया जा सके। योगदान के तहत एनसीसी कैडेटों के लिए निर्धारित कार्यों में , हेल्पलाइन / कॉल सेंटर का प्रबंधन; राहत सामग्री / दवाओं / खाद्य / आवश्यक वस्तुओं का वितरण; सामुदायिक सहायता; डेटा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए कतार में खडे होने की व्यवस्था करना तथा यातायात प्रबंधन शामिल है।

कोरोना पर केन्द्रित फर्जी खबरों को फैलने से रोकने उचित कदम उठाएं

» गृह मंत्रालय की राज्यों को सलाह

नईदिल्ली (आरएनएस)। एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने फर्जी खबरों के चलते बढ़ी परेशानियां और इस क्रम में प्रवासी कामगारों के व्यापक स्तर पर पलायन को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने माना कि इससे लोगों को बेवजह मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।

न्यायालय की टिप्पणियों के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को पत्र लिखकर फर्जी खबरों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। इसमें कहा गया कि भारत सरकार लोगों को तथ्यों और असत्यापित खबरों की पुष्टि की खबरों की सुविधा देने के लिए एक वेब पोर्टल तैयार कर रही है। राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों से इससे संबंधित समस्याओं के लिए अपने स्तर पर ऐसा ही एक तंत्र विकसित करने का अनुरोध भी किया गया है।

भारत सरकार को 100 करोड़ का मेडिकल उपकरण दान करेगा टिकटॉक

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस महामारी के बीच चीनी वीडियो शेयरिंग और सोशल नेटवर्किंग ऐप टिक टॉक ने भारत में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए 100 करोड़ रुपये के मेडिकल उपकरण दान किये जाने का निर्णय लिया है।

टिक टॉक न्यूज रूम के मुताबिक इसमें 400000 हैजमेट

सूट्स (प्रोटेक्टिव सूट्स) और 200000 मास्क शामिल होंगे। सोशल नेटवर्क सर्विस इस आशय कि जानकारी देते हुए बताया कि वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को यह उपकरण देने के लिए कपड़ा मंत्रालय के साथ काम कर रही है।

कंपनी ने आगे कहा कि आने वाले समय में टिक टॉक और अधिक दान कर सरकार को मदद करने के लिए तैयार है। टिक टॉक ने अपने बयान में कोरोना महामारी के समय डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के महत्व को परिभाषित करते हुए कहा कि वे वायरस से सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं और उनके एक्सपोज होने की ज्यादा संभावना रहती है। इनकी सेफ्टी के लिए हम 400000 हैजमेट (मेडिकल प्रोटेक्टिव सूट्स) भारत सरकार को दान कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ,राज्यपालों, एलजी एवं राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ कोरोना रिस्पांस पर चर्चा करेंगे

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 अप्रैल राष्ट्रपति भवन से उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ कोविड-19 प्रकोप से उत्पन्न संकट को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु राज्यपालों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों एवं सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस आयोजित करेंगे।

राज्यपालों/लेफ्टिनेंट गवर्नरों एवं राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ यह इस प्रकार का दूसरा वीडियो

कांफ्रेंस होगा। 27 मार्च, 2020 को आयोजित पहले वीडियो कांफ्रेंस में 14 राज्यपालों एवं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने क्षेत्रों के अनुभव को साझा किया था। शेष राज्यपाल/लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं प्रशासक कल अपने अनुभव साझा करेंगे।

कांफ्रेंस के एजेंडा में राज्यों में कोविड-19 की स्थिति, निर्बल वर्गों पर फोकस के साथ रेड क्रास की भूमिका, एवं नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने में सिविल सोसाइटी/ स्वयंसेवी संगठनों/निजी क्षेत्र की भूमिका शामिल होगी।

» सरकार ने लॉकडाउन में सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत करने को उठाया कदम

कोरोना के चलते दिल्ली में केंद्रीय बलों की 100 कंपनियां तैनात

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत करने के लिए राजधानी दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती बढ़ाते हुए सौ कंपनियों को तैनात किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की एक कंपनी में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को आदेश जारी कर दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन कंपनियों में करीब 10,000 जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। अधिकारी ने बताया कि फरवरी से अलग-अलग बैचों में राष्ट्रीय राजधानी में इन इकाइयों को तैनात किया गया था। तैनाती 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई गई है। इन 100 कंपनियों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 41, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की 7, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 17, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की 6, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 16 और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 13 कंपनियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च की मध्यरात्रि से देशभर में 21 दिन के बंद की घोषणा की थी।

पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, मांगे सुझाव

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की।

इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा की और सुझाव दिए। उन्होंने राज्य सरकारों को आश्वासन दिया कि उनके साथ केंद्र खड़ा है और हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की चिंता लॉकडाउन को लेकर दिखी। उन्होंने हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने की अपील की. साथ ही कहा कि लोगों को जरूरी सामान भी मुहैया कराए जाएं, ताकि किसी को दिक्कत न आए। मजदूरों के पलायन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि हमें हर संभव पलायन को रोकना होगा। इसके लिए हर राज्य अपने ओर से सारे इंतजाम करे। मजदूरों के लिए शेल्टर होम के साथ उनके खाने-पीने की व्यवस्था की जाए। वहीं मजदूरों से

अपील की जाए कि वह सड़कों पर न निकलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकारों के बेहतरीन समन्वय की जरूरत है। केंद्र सरकार हर राज्य के साथ खड़ी है और उन्हें जरूरी मदद उपलब्ध कराई जाएगी. इस दौरान पीएम मोदी ने राज्यों से मेडिकल सुविधाओं के बारे में भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों में बढ़े कोरोना मरीजों की तादाद पर चिंता जाहिर की।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों में भी सिम्टम्स दिखे उन्हें आइसोलेट किया जाए। वहीं संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारनटीन किया जाए. अगर क्वारनटीन वार्ड बढ़ाने की जरूरत है तो उसे बढ़ाया जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) बढ़ाने के टिप्स दिए थे. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि आयुष मंत्रालय ने बेहतर स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए कुछ दिशानिर्देश दिए हैं। ये ऐसे उपाय हैं, जो आसानी से किए जा सकते हैं। कई तो ऐसी बातें हैं, जो मैं खुद वर्षों से कर रहा हूं। जैसे पूरे साल सिर्फ गर्म पानी पीना। कोरोना से बचाव के टिप्स देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, साथ ही दूसरों के साथ भी साझा करें। पीएम मोदी ने अपने संदेश के साथ आयुष मंत्रालय के दिशानिर्देशों से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की है।